

SHRI ARIF MOHD. KHAN: I am sorry, Sir, I forgot the second part, about the National Integration Council. I have already stated in the main reply that the matter is receiving the attention of the Government. The last meeting was held in 1982.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय मान्यवर, यह बात अब सिद्ध हो चुकी है कि जिनो भी सांप्रदायिक दंगे हुए है और उनमें से कुछ ऐसे भी सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, जिनका मूल कारण गृहा है, जो धार्मिक स्थल हैं या पूजा स्थल है, चाहे बड़ मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो या कोई और पूजा स्थल हो, वहाँ पर अल्पवयों को अरण देना और उनका दुरुपयोग करना निहित राजनीतिक उद्देश्यों को पूर्ति के लिए। तो मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार भविष्य में सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए और पूजा-स्थलों, धार्मिक स्थलों का दुरुपयोग न हो, इसके लिए कोई कानून डम मदन में लाएगी?

श्री अरिफ मोहम्मद खान : सरकार की पूरी कोशिश यही है कि धार्मिक-स्थलों का उपयोग सांप्रदायिकता फैलाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए बल्कि उसी उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए, जिसके लिए यह धार्मिक-स्थल बने हुए हैं। सरकार इस पर पूरी चोक्मी बरत रही है। अब जो सम्मानित सदस्य ने कहा है कानून का, उनका यह मुझसे श्रीमन्, मैं नोट किए लेता हूँ।

MR. CHAIRMAN: Next question.

#### Setting up of a National Science and Technical Information network

\*245. SHRIMATI KRISHNA KAUL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government propose to set up a National Science and Technology Information network in the country; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE PARLIAMENTARY SECRETARY (SHRI ARUN SINGH): (a) Yes, Sir.

The programme of National Information System for Science and Technology (NISSAT) was initiated in 1977.

(b) Initially, four sectoral information centres on machine tools, leather, food technology and drugs and pharmaceuticals, and a datacentre on crystallography were set up. Modern technologies of on-line connection with remote databases and computer based selective dissemination of information were demonstrated; several short-term courses, seminars and exhibitions were organised. During the Seventh Five Year Plan, it is proposed to expand the activities and develop the network.

SHRI PARVATHANENI UPENDRA: Maiden answer.

MR. CHAIRMAN: This is his second answer. The maiden answer was given earlier. You cannot go on calling him a maiden every time.

SHRIMATI KRISHNA KAUL: The National Council for Science and Technology Communication has approved the setting up of a National Science and Technology Information network to popularise science. May I know as to how or in what way this network will help in the development of field-level projects in science and technology in order to popularise science and technology and inculcate a scientific temper among the people, specially those living in the rural areas?

SHRI SHIVRAJ PATIL: This Science and Technology Communication Council is proposing to publish some newsletters and some magazines and some literature in a simple language, in the layman's language, which can be understood by the common man. And in that kind of literature, information about the technology which will be useful to the people living in rural areas and carrying on domestic and small-scale industries, will be given. An attempt is made to simplify the technical information into languages which can be easily understood by them.

SHRIMATI KRISHNA KAUL: Is it true that in order to expand the activities and develop the network the National

Council has also proposed to institute awards for the best newspaper coverage of scientific activity, the best scientific film, the best do-it-yourself kit and the 'best scientific toy'. This proposal is most commendable, especially the inclusion of the best scientific toy because the children will acquire scientific information and knowledge in a play-way. I would like to know whether the National Council is also proposing to set up a committee to decide those awards.

**SHRI SHIVRAJ PATIL:** The idea is commendable. We will consider it. And if we accept it, a committee has to be there.

**श्री हनुमन् देव नारायण यादव :** सभापति महोदय, मैं सरकार में यह जानना चाहता हूँ कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की जो सूचनाएँ हैं वह ग्राम लोगों तक पहुँच सकें इस के लिये क्या सरकार इन सूचनाओं को जनता की लोक भाषा में पहुँचाने का काम कर रही है या सरकार इस को ऐसी भाषा में छपाना चाहती है किताब के रूप में कि ग्राम जनता तक वह पहुँच ही न पाये और जिन देशों में दो तिहाई लोग निरक्षर हों, दो अक्षर भी जिन का ज्ञान नहीं उस देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिये लोगों को साक्षर करना पहले जरूरी है। वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकें इस के लिये उन को जल्दी से जल्दी साक्षर होना चाहिए और आप के ज्ञान और विज्ञान की बातें उन के लिये काला अक्षर, भ्रम बराबर न रह जायें तो क्या इस पर सरकार विचार करेगी और क्या वह इस के लिये कोई योजना बनायेगी ?

**श्री शिवराज पाटिल :** मैंने पहले ही जवाब में कहा था कि विज्ञान और तकनीक का ज्ञान ऐसी भाषा में लोगों तक पहुँचाना चाहिए जो वे समझ सकें। हमारा प्रयास है कि वह ऐसी भाषा में हों कि जिन लोग आसानी से समझ सकें। वह ज्ञान सिर्फ अंग्रेजी में ही नहीं बल्कि हिन्दी भाषा में और हमारी अन्य प्रान्तीय भाषाओं में भी उन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस का माध्यम केवल लिखित माध्यम ही नहीं होगा, बल्कि जिस को हम

आडियो विजुअल कहते हैं, जिस में देखते और सुनते हैं, ऐसी फिल्म बना कर हम उन तक यह ज्ञान पहुँचाने की कोशिश करते हैं ताकि वह ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी इन चीजों को समझ सकें।

**श्री सत्यपाल मलिक :** श्रीमान्, साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में हिन्दुस्तान ने बहुत प्रगति की है। अभी हम लोग इनसेट का जिक्र कर रहे थे लेकिन कुछ चीजें हैं जिनके बारे में देश के गरीब आदमी को जानकारी देनी चाहिए। अभी जो बैलगाड़ी देश में इस्तेमाल होती है उस में पिछले 20, 30 साल से कोई इन्वेंशन नहीं हुआ है जिसे उस में बैलों की पावर का मिस्यूज होता है। उस को बचाया जा सकता है। हमारे रहट पानी खींचने के लिये इस्तेमाल होते हैं। पिछले 20 साल से उस का लीवर बिल्कुल वैसा ही है, उसकी पुली वैसी ही है। उस में कोई इन्वेंशन नहीं हुआ है। मैं जानना चाहता हूँ कि जो जन जीवन में ताल्लुक रखने वाली चीजें हैं उन में सुधार के लिये हमारे वैज्ञानिकों ने क्या किया है ? क्या आप ग्राम पंचायत के लिये यह कन्सरी कर देंगे कि वे इन सब की जानकारी हर महीने गांव के लोगों को बुला कर दें। हाउसिंग के मामले में, साइंस के मामले में, विजली के मामले में, इनर्जी के मामले में जो गांव की पंचायतें हैं उन के प्रधान और मैकेटरी के द्वारा इस ज्ञान को देने की व्यवस्था की जाय। और इसको देखा जाय कि वह यह करते हैं या नहीं। मैं माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा कि क्या यह संभव हो सकेगा कि हर पंचायत को आप यह जिम्मेदारी दें।

**श्री शिवराज पाटिल :** श्रीमान्, हमारे देश की नीति है कि अच्छी से अच्छी और जिसको महत्वपूर्ण और सॉफ्टवेयर और बड़ी हुई टेक्नोलॉजी कहते हैं, उसका हम इस्तेमाल करें। उसके साथ साथ हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में हमने यह भी बताया है कि जो रेलेवेन्ट टेक्नोलॉजी लोगों के उपयोग में आने वाली टेक्नोलॉजी है उसको भी बढ़ाकर हम देते हैं। यह जो काम

हमारी लैबोरेटरीज में अलग-अलग जगहों पर हो रहा है, उसकी मालूमात हम भिन्न भिन्न माध्यमों से लोगों तक पहुंचाते हैं। यह काम तेजी से हो, इसलिए हमने हर स्टेट गवर्नमेंट को लिखा है कि वह साइंटिफिक कौंसिल बनाए, साइंटिफिक डिपार्टमेंट बनायें और उनकी जो मशीनरी है उससे वह जिला, ताल्लुका और गांव के स्तर तक उसको पहुंचाया जाय ताकि यह काम जल्दी में जल्दी हो सके। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यह सारा ज्ञान उन तक पहुंचाने के लिये मशीनरी नहीं है, इस वजह से हम स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी की मदद ले रहे हैं। आपका मुझाब अच्छा है। इस प्रकार से प्रयास किया गया है और उसका उपयोग किया जा रहा है। टैक्नालाजी हमारे पास है लेकिन उसको रूपान्तरित करके उसको पहुंचाने तक का जो काम है उसको भी बढ़ाना जरूरी है। बैलगाड़ी तो अच्छी यनी है, मगर उसका ज्यादा संख्या में निर्माण करना चाहिए।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over now.

### WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

#### Ban on foreign tourists visiting certain tourist spots in West Bengal

\*246. SHRIMATI KANAK MUKHERJEE: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the foreign tourists have been debarred from visiting some of the tourist spots in West Bengal; and

(b) if so, what are the details thereof and what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRIMATI RAM DULARI SINHA): (a) and (b) Five northern districts of West Bengal, namely, Darjeeling, Cooch Behar, Jalpaiguri, Malda and West Dinajpur have been declared as restricted areas under the Foreigners (Restricted Areas) Order, 1963. Therefore foreigners cannot visit these places without taking special permission.

This has been done for security reasons. However, adequate relaxations have been made for allowing foreign tourists to visit certain tourist spots falling within this area.

#### Route rationalisation of the three services of airlines

\*247. SHRIMATI MONIKA DAS: Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to the reply to Unstarred Question 1021 given in the Rajya Sabha on the 9th May, 1985 and state:

(a) whether the Committee appointed to study and recommend route rationalisation of the services of the three airlines, Air India, Indian Airlines and Vayudoot, has since submitted its report to Government; and

(b) if so, what are the salient features of the report?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL AND TRAINING, ADMINISTRATIVE REFORMS AND PUBLIC GRIEVANCES AND PENSION AND IN THE DEPARTMENT OF CULTURE (SHRI K. P. SINGH: DEO): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

#### ad-hoc Licences for setting up industrial units by Family members of Delhi Mayor

\*248. SHRI SHANKER SINH VAGHELA:

SHRI VIRENDRA VERMA:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the recent press reports appearing in certain section of the Press regarding cheating the Delhi Municipal Corporations by the family members of Delhi Mayor in getting ad-hoc licences for setting up industrial units on certain plots in Anand Parbat on false declarations; and